



डॉ० राजीव कुमार श्रीवास्तव

असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
समन्वयक – उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय
नोडल अधिकारी, इण्डियन स्पेस वीक
श्री सुदृष्टि बाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुदृष्टिपुरी-रानीगंज
बलिया 277208 (उ०प्र०) भारत

शिक्षा

- एम०ए० (प्राचीन इतिहास-1997) रेल ट्रान्सपोर्ट इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली।
- एम०ए० (समाजशास्त्र-2002)
- एम० फिल० (समाजशास्त्र- शीर्षक: भारतीय प्रशासन एवं वर्तमान सामाजिक सम्बन्ध) महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- पी-एच० डी० (समाजशास्त्र) शीर्षक : भारतीय पुलिस प्रशासन एवं वर्तमान सामाजिक सम्बन्ध के प्रति सामान्यजन, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के दृष्टिकोण) महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

प्रशस्ति पत्रा

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली, यूजीसी एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन (यू०के०) के शैक्षणिक यात्रा के लिए चयनित (21-28 नवम्बर, 2015 तक, डॉ० अम्बेडकर के 125 वीं जयन्ती पर)

सम्मान

- Awarded by I2OR Publication Excellence Award 2018, From Melborn, Austrellia and CII Chandigarh, India
- I2OR Excellence International Journal Award 2019
- GLOBAL PUBLISHER AWARD 2021
- GURU International Pride Award 2022- Kathmandu (Nepal)
- Global Dimond Icon Award 2026, Jaipur, Rajasthan

सम्पादकीय

सरकार का जेनजी की ओर रुझान: बदलती युवा आकांक्षाएँ और लोकतांत्रिक राजनीति की नई दिशा
वर्तमान समय में जेनजी (Generation Z) अर्थात् नई युवा पीढ़ी की भूमिका भारतीय राजनीति, समाज और शासन व्यवस्था में लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। सामान्यतः 1997 से 2012 के बीच जन्मी पीढ़ी को जेनजी कहा जाता है। यह पीढ़ी डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, सोशल मीडिया और वैश्विक विचारों के बीच विकसित हुई है। इसकी आकांक्षाएँ, सोचने का तरीका और राजनीतिक अपेक्षाएँ पिछली पीढ़ियों से कई मायनों में भिन्न हैं। ऐसे में सरकार का जेनजी की ओर बढ़ता रुझान केवल युवाओं को आकर्षित करने की राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश की आवश्यकता भी है।

भारत विश्व के सबसे युवा देशों में शामिल है। यहाँ युवाओं की विशाल आबादी देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक व्यवस्था को नई दिशा देने की क्षमता रखती है। जेनजी रोजगार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी विकास, उद्यमिता, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मुद्दों को विशेष महत्व देती है। यह पीढ़ी केवल सरकारी घोषणाओं से संतुष्ट नहीं होती, बल्कि उनके वास्तविक परिणामों को भी परखती है। इसलिए सरकारों के लिए युवाओं की अपेक्षाओं को समझना और उन्हें नीतियों के निर्माण में उचित स्थान देना अनिवार्य हो गया है।

सरकार का जेनजी की ओर रुझान कई स्तरों पर दिखाई दे रहा है। डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कौशल विकास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने वाली पहलों का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। तकनीकी नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विस्तार ने युवाओं के सामने नए अवसरों के साथ नई चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं।

हालाँकि, सरकार और जेनजी के संबंधों का वास्तविक मूल्यांकन केवल योजनाओं और प्रचार अभियानों के आधार पर नहीं किया जा सकता। युवाओं के सामने बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिश्चितता, महँगी शिक्षा, आर्थिक असमानता और मानसिक दबाव जैसी समस्याएँ मौजूद हैं। बड़ी संख्या में युवा अपनी योग्यता के अनुरूप रोजगार प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में यदि सरकार जेनजी को केवल चुनावी समर्थन प्राप्त करने वाले समूह के रूप में देखती है, तो यह दृष्टिकोण दीर्घकालीन दृष्टि से प्रभावी नहीं होगा।

जेनजी की एक प्रमुख विशेषता इसकी डिजिटल सक्रियता है। सोशल मीडिया ने युवाओं को अपनी राय व्यक्त करने, सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और सरकार से जवाबदेही की माँग करने का प्रभावशाली मंच बन गया है। अब नागरिक केवल पारंपरिक माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करके अपने निष्कर्ष निकाले लगे हैं। सरकार के लिए यह परिवर्तन अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि डिजिटल माध्यमों से जनसंवाद अधिक व्यापक बनाया जा सकता है; चुनौती इसलिए कि भ्रामक सूचनाएँ, अफवाहें और आक्रामक राजनीतिक प्रचार युवाओं की सोच को प्रभावित कर सकते हैं।

अतः सरकार को डिजिटल साक्षरता, तथ्यपरक संवाद और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह भी ध्यान देने योग्य है कि जेनजी कोई एकसमान राजनीतिक या सामाजिक समूह नहीं है। ग्रामीण और शहरी युवाओं, विभिन्न आर्थिक वर्गों, महिलाओं, विद्यार्थियों तथा रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं की समस्याएँ अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए सरकार की नीतियाँ युवाओं की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार के अवसरों का विस्तार, सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, कौशल प्रशिक्षण की गुणवत्ता तथा युवाओं के लिए सुलभ उद्यमिता व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं।

सरकार को युवाओं के प्रति अपना रुझान केवल संवाद कार्यक्रमों, सोशल मीडिया अभियानों या आकर्षक नारों तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

नीति निर्माण में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में सार्थक विमर्श को राष्ट्र निर्माण में सहभागी नागरिक मानना आवश्यक हो गया है।

डॉ० राजीव कुमार श्रीवास्तव

प्रधान सम्पादक